nwda.gov.in

गुणवत्ता बरकरार रखते हुए तय समय में यमुना का करें कायाकल्प : एलजी

उपराज्यपाल ने यमुना नदी की सफाई को लेकर समिति की दूसरी बैठक ली

- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा यमुना की सफाई को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया
- 20 जनवरी को हुई समिति की पहली बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति की हुई समीक्षा

यमुना नदी की सफाई को लेकर एनजीटी द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक लेते एलजी वीके सक्सेना ● सौ. राजनिवास

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने गुणवत्ता से समझौता किए बगैर तय समय में यमुना नदी का कायाकल्प करने के लिए कहा है। साथ ही इस दिशा में तय लक्ष्यों को भी समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस आशय की जानकारी मंगलवार को उन्होंने ट्वीट करके दी।

दरअसल, मंगलवार को एलजी ने यमुना नदी की सफाई को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव, सिंचाई, वन एवं पर्यावरण, कृषि और वित्त विभागों के सचिव, केंद्रीय कृषि, पर्यावरण और जल शक्ति मंत्रालयों के सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक सहित अन्य हितधारक भी शामिल रहे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया। बता दें कि एलजी की अध्यक्षता में एनजीटी ने नौ जनवरी को उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।

राजनिवास में हुई इस बैठक में 20 जनवरी को हुई समिति की पहली बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। एलजी ने अधिकारियों से कहा कि यमुना नदी में गिरने वाले नालों की सफाई, सीवर लाइन से गाद निकालने, एसटीपी के निर्माण, सेप्टेज प्रबंधन आदि के लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने गुणवत्ता से समझौता किए बिना सभी कार्यों को पूरा करने पर भी जोर दिया।

उन्होंने यमुना नदी के मुख्य प्रदूषक नजफगढ़ नाले में बहते नालों से गाद निकालने और दोहन में अब तक के कार्यों पर संतोष जताया और शाहदरा नाले में इसी तरह के प्रयास दोहराने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हाथ में लिया गया कार्य कठिन है, लेकिन मुश्किल नहीं है। उन्होंने प्रतिबद्ध समय-सीमा को बढ़ाए बिना मिशन मोड में निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया। साथ ही कहा कि अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की कमी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि यमुना के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक में यमुना नदी सफाई के लिए संबंधित विभागों में आठ मानकों पर छह महीने की कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनाई गई थी। इसमें सीवेज उपचार को बढ़ाना, अनधिकृत कालोनियों में सीवर नेटवर्क बिछाना और नदी के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में बहाल करना भी शामिल है।